It is a very very small number. It has to be increased. Then only there could be an improvement in the condition of disabled people. It has also been mentioned in the statement that the Government has also reserved 3 per cent vacancies for the disabled people. It appears that even 3 per cent reservation has not been fulfilled. The Statement itself shows, according to the figures, that it has not been implemented. Will the hon. Minister assure that at least those persons who are physically disabled, who have been given the vocational guidance and who have been suffering a lot will be rehabilitated?

SHRI P. K. THUNGON: It is a fact that there are 14 rehabilitation centres. I would like to tell the hon. Member that during the last three years how many disabled persons have been rehabilitated. In 1980, it was 2,781; in 1981, it was 3,914 and, in 1982, it was 4,510. This shows that there has been an upward increase and that is the proof of our effort that we are trying our level best to improve the conditions of the handicapped people and how best we are giving more facilities to the disabled people in the country. It is very difficult to cover all the disabled people because the problem is very gigantic in a country of our size and population.

Regarding the 3 per cent reservation for the handicapped people, so far as the Central Government is concerned, we have employed 5,700 persons and another 2,600 persons in Centrally sponsored public sector undertakings.

SHRI OSCAR FERNANDES: The Government has spent huge sums of money in giving aid to the physically handicapped people. There are a number of cases where, if surgery is performed, these physically handicapped people can get back their limbs to walk and even to work. I would like to know from the hon. Minister whether the Government has formulated any scheme of conducting surgery so that the physically handicapped people are able to get back their limbs, to enable them to work normally. Is the Government doing anything in that regard?

SHRI P. K. THUNGON: We have already got a scheme for providing artificial limbs to the handicapped persons. So far as the surgery is concerned, that is to be performed by doctors. In some cases of those who are economically weak, free artificial limbs are provided and in the case of those who are economically a little better off, only a certain percentage of cost is charged from them.

SHRI OSCAR FERNANDES: That is not my question at all. When surgery is performed, a person can get back his power of working. I am asking whether the Government can give some financial assistance in such cases for surgical operation.

श्री गिरधारी लाल व्यास: अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि आई.ए.एस. और आई. पी. एस. अधिकारियों के तथा जो गवर्नमेन्ट सर्विस में कार्यरत हैं, उनके कितने लड़के-लड़कियां विकलांग हैं और उनमें से कितने लड़के-लड़कियों को आपने रोजगार दिया है, कृपया बताएं ?

श्री पी. के. थुंगन: आनरेबल मेम्बर ने बहुत जटिल प्रश्न पूछा है, इसके बारे में अभी तक हमने तर्क-आउट नहीं किया है।

श्री गिरधारी लाल व्यास: आइ. ए. एस. और आई. पी. एस. अधिकारी तो आपके हैं ।

श्री पी. के. थुंगन: आनरेबल मेम्बर ने जो पूछा है वह अगर दुबारा पूछ लें तो मैं छान-बीन करके बता दूंगा ।

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

भारतीय मालवाहक जहाज एम. वी. मारजन का डूब जाना

*452. **श्री जगपाल सिंह**:
श्री आर. पी. गायकवाड़:

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि भारतीय मालवाहक जहाज एम. वी. मारजन बहरीन से कांडला पत्तन आते हुए फरवरी के अन्तिम सप्ताह में डूब गया था;

(ख) यदि हां, तो नाविकों सहित कितने व्यक्तियों के मरने की आशंका है और कितने शव अब तक निकाल लिए गए हैं और पहचान कर लिए गए हैं;

(ग) क्या मृतकों के परिवारों को सरकारी तौर पर सूचित कर दिया गया है;

(घ) यदि नहीं; तो ऐसा करने में सरकार को क्या कठिनाइयां हो रही हैं;

(ङ) मृतकों के परिवारों को सहायता देने के लिए सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है;

(च) क्या सरकार मृतकों के प्रत्येक परिवार को दो लाख रुपये का मुआवजा देने पर विचार कर रही है; और

(छ) यदि हां, तो यह राशि कब तक वितरित कर दी जाएगी ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री के. विजय भास्कर रेड्डी): (क) जी, हां ।

(ख) जिन 31 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने की आशंका थी, उनमें से 16 के शव प्राप्त कर लिए गए हैं । इनमें से 12 शवों की शिनाख्त कर ली गयी है ।

(ग) और (घ). जहाज मालिक और शिपिंग मास्टर, बम्बई ने इस दुर्घटनाग्रस्त जहाज के कर्मीदल के निकटतम सम्बन्धियों को सूचित कर दिया है ।

(ङ) से (छ). नाविक संघों और नियोक्ताओं के बीच द्विपक्षीय करार के अनुसार ही कर्मीदल के सदस्यों को मुआवजा दिया जाता है । सरकार दो लाख रुपये का मुआवजा देने के किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है ।

नौवहन कंपनियों के कार्यकरण के बारे में पद्मनाभन समिति का प्रतिवेदन

*श्रीमती किशोरी सिन्हा:
श्री रवीन्द्र वर्मा:

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने **नौवहन कंपनियों के कार्यकरण की जांच** करने के लिए पद्मनाभन समिति गठित की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस समिति का प्रतिवेदन इस बीच प्राप्त हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री के0 विजय भास्कर रेड्डी): (क) भारत के विदेश व्यापार में ट्रम्प प्रचालकों के घिनौने क्रियाकलाप का अध्ययन करने के लिए पद्मनाभन समिति गठित की गयी थी ।

(ख) जी, हां।

(ग) समिति ने ग्यारह सिफारिशें की जिसमें से नौ सामान्य किस्म की थीं। अन्य दो सिफारिशें नौवहन एजेंटों को लाइसेंस देने की पद्धति शुरु करने और बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और कोचीन के चार महापत्तनों में स्थायी समितियां गठित करने से संबंधित थीं ।

एक को छोड़कर सभी सिफारिशों को मान लिया गया है और इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है । अभी एक सिफारिश पर निर्णय नहीं किया गया है ।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के दैनिक मजूरी पर काम करने वाले कर्मचारियों को नियमित करना

*455. **श्री राम सिंह शाक्य:** क्या **शिक्षा और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय देश भर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की विभिन्न सभी शाखाओं, स्मारकों और पार्कों में कर्मचारी दैनिक मजूरी पर कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो दैनिक मजूरी पर काम करने वाले कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाया गया है; और

(ग) दैनिक मजूरी के ऐसे कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने में वास्तव में कितनी प्रगति हुई है?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी. के. थुंगन): (क) जी हां ।

(ख) दैनिक मजदूरों की सेवाओं को नियमित करने का मानदण्ड वही है जो गृह मंत्रालय के अनुदेशों में निहित है । संक्षेप में वे इस प्रकार है*:-